मैं यह लाना चाहता हूं कि छतरपुर, दिल्ली में विदेश संचार निगम लिमिटेड को किसानों से अधिगृहीत कर के सांस्थानिक (इंस्टीटयुशनल) प्रयोग हेतु एक भूखंड आवंटित किया गया था। एक निजी कम्पनी उक्त भूखंड पर डीटीएच सर्विसेज चलाने हेतु अपना कार्यालय स्थापित करने जा रही है तथा उसने संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से WPC लाइसेंस देने तथा SACFA क्लीयरेन्स देने हेतु प्रार्थना की है।

महोदय, सांस्थानिक भूमि का व्यावसायिक प्रयोग सरासर दुरुपयोग है। इसलिए मेरी मंत्री जी से मांग है कि ऐसी कंपनी का सांस्थानिक भूमि पर कदापि व्यावसायिक गतिविधियां चलाने की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए। और उन्हें WPC लाइसेंस तथा SACFA क्लीयरेन्स नहीं दी जानी चाहिए। धन्यवाद।

Demand to save wild life in various sanctuaries in the Country

SHRI LEKHRAJ BACHANI (Gujarat). : Sir, my Special Mention relates to the need for saving wild life in Govenrment sanctuaries. Recently, it was reported that tigers, elephants and other animals were being killed by poachers for business and other purposes. Even in the Gir forest of Gujarat lions are being killed by giving poisoned meat.

No extensive efforts are being done to save wild life and whatever efforts are being made by the forest department are not enough and satisfactory.

India is very weak in preserving wild life as compared to other countries. The first thing is that the Governemnt should recruit more forest guards. In the last 20 years, no forest guards have been recruited. The average age of a forest guard is 50 years. The number of vacancies is very large. The forest is full of natural treasures and this aged forest staff are unfit to patrol and enforce the laws.

In South India, sandalwood and ivory are highly valued and that is why it is necessary to guard the forests against the timber and ivory *mafias*. Hence, we must also provide better and necessary training to the people and the forest staff so that they can tackle the forest *mafias*. Politicians and bureaucrats should come forward actively for tackling these problems. The media can also play vital role by dedicating some space in their newspapers and journals, and including environmental and wild life issue in their editorials.

It is, therefore, requested that the Government of India should start a much more successful and effective all-round mission to save the wild life in the country. Thank you.

To develop National Highways in Orissa

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे विशेष उल्लेख का विषय है-उड़ीसा के राजमार्गों के विकास हेतु मांग।

महोदय, सन् 2000 से उड़ीसा उद्योग की दृष्टि से भी आगे बढ़ रहा है। पहले मुख्यतया यह एक कृषि आधारित प्रांत था, लेकिन आज पब्लिक सैक्टर के साथ-साथ विदेशी पूंजी निवेशक भी प्रदेश में काफी मात्रा में आ रहे हैं। अपने देश के घरेलू निवेशकों ने भी वहां उद्योग बैठाना चालू कर दिया है। इसका एक मुख्य कारण है कि इस प्रदेश की जनता बहुत शांतिप्रिय है। मात्र इस व्यापक औद्योगिकीकरण के कारण अगर उन्हें यातायात हेतु राजपथ, ग्रामपथ यानी कि रोड-रास्ता भी न मिले, तो यह कितने दिन तक सहनीय होगा।

महोदय, 1998 से पहले तो प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग नाममात्र का ही था, उसके बाद धीरे-धीरे कई मार्गों को राजमार्ग का दर्जा दिया गया, प्रशस्तीकरण तथा विकास के लिए कुछ पैसा दिया गया, लेकिन अब शायद वह कार्य प्राय: ठप हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 215, जो कि याजपुर जिले के पाणिकीइलि से सुंदरगढ़ जिले के राजामुंडा तक व्याप्त है, राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 23, जो कि अनुगुल जिले के बंअरपाल से राउरकेला होता हुआ झारखंड प्रदेश में रांची तक गया है, इन दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत भी अत्यंत खराब है। कथित दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों का इस्तेमाल कोयला तथा ऑयरन-ओर के परिवहन के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 200 की हालत भी अत्यंत खराब है। इन तीन राष्ट्रीय राजमार्गों के द्रुत विकास हेतु मैं सरकार के सामने पुरजोर मांग रखता हूं, विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 200 के भुवन-कामारण्यानगर खंड के प्रति तुरंत ध्यान दिया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 42, जो कि सांस्कृतिक राजधानी कटक और पश्चिमी उड़ीसा के प्रमुख शहर संबलपुर को जोड़ता है, का भी 4 लेनिंग का काम प्रारम्भ किया जाना चाहिएं। इसी मार्ग पर हाल के दो साल में ऐक्सिडेंट्स में दो विधायकों की जानें गई है। इसी राजमार्ग पर पड़ने वाले अनुगुल शहर के लिए बाइपास की भी व्यवस्था तुरंत की जानी चाहिए। राजमार्गों की बदहाली से जनता बहुत परेशान है, अत: युद्धस्तर पर इनकी मरम्मत, विकास, 4 लेनिंग, बाइपास निर्माण आदि कार्य हेतु आवश्यकता पड़ने पर निवेशकों से भी वार्ता की जानी चाहिए।

कैसे भी हो, राज्य के राजमार्गों का तुरंत विकास किए जाने हेतु मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के सामने दृढ़ दावा करता हूं।